किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु गुजरात को आर्थिक सहायतक दिया जाना

4227. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु गुजरात राज्य सरकार को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई;

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए आर्थिक सहायता हेतु कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई; और

(ग) राज्य सरकार को यह धनराशि कब तक दे दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशी दवाओं जैसे आदानों की खरीद करके उन्हें किसानों को सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए रबी तथा खरीफ के मौसमों में अलग-अलग लघु अवधि ऋण प्रदान किए जाते रहे हैं। वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान गुजरात सरकार को दी गई ऋण सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ऋण सहायता
1991-92	14.65
1992-93	12.70
1993-94	6.85
	(केवल खरीफ मौसम के लिए)

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Ban on Cow Slaughter

4228. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the names of the States where cow slaughter has been completely or partially banned and since when the ban has been in force;

(b) what is the total number of incidents of cow slaughter which occurred in violation of such ban during the year 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94 alongwith the State-wise number of persons against whom action has been taken in this regard;

(c) whether Government propose to frame an effective legislation to put a complete ban on cow-slaughter; and

(d) if so, by when such a legislation is likely to be framed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) A statement is enclosed (*see* below).

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) The subject of preservation of cattle is a matter on which only the State Legislatures have exclusive powers to legislate. Accordingly, various State Governments have suitable laws relating to prevention of slaughter of cow and its progeny.

(d) In view of (c) above question does not arise.

Statement

Name of the State where cow slaughter has been completely or partially banned and the year of such ban.

Sl. No.	Complete ban	Partial ban
1.	Andhra Pradesh—Completely banned since 1977.	1. Assam— Partially banned since 1961.
2.	Bihar-Completely banned since 1956.	2. Orissa—Partially banned since 1960.
3.	National Capital Territory of Delhi — Completely banned since 1966.	
4.	Goa — Completely banned since 1979.	

Sl. No.	Complete ban	Partial ban
5.	Gujarat — Completely banned since 1979.	
6.	Haryana — Completely banned since 1955.	
7.	Himachal Pradesh — Completely banned since 1979.	
8.	Jammu & Kashmir — Completely banned since Maharaja's rule.	
9.	Karnataka — Completely banned since 1964.	
10.	Madhya Pradesh — Completely banned since 1959.	
11.	Maharashtra — Completely banned since 1978.	
12.	Punjab — Completely banned since 1955.	
13.	Rajasthan — Completely banned since 1950.	
14.	Sikkim — Completely banned since 1925.	
15.	Tamil Nadu — Completely banned since 1976.	
16.	Tripura — Completely banned when ever prior to the State's accession to the Indian Union.	
17.	Uttar Pradesh — Completely banned since 1956.	

सहकारी बैंकों को दीर्घावधि ऋण

4229. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 16 कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कालातीत ऋणों के कारण हुए नुकसान हेतु दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(ख) इन प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि योग्य क्षेत्र

4230. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 184 मिलियन हेक्टेयर है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1996 तक 113 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर पाने की संभावना व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त आयोग ने हाल ही में पुनर्विचार करने के बाद सिंचित हो पाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो इस समय इस भूमि का क्षेत्रफल कितना है; और

(च) क्या सरकार ने सिंचित की जा सकने वाली सम्पूर्ण भूमि को सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) से (ङ) सकल सिंचित क्षेत्र के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग के मतानुसार सिंचित क्षेत्र (सतही तथा भूगत जल दोनों) 1995 में अनुमानत: 77 मिलियन हैक्टेयर होगा और 2000 ईसवी तक यह 84 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान है। 2005 ई. तक इस क्षेत्र को 110 मिलियन हैक्टेयर किए जाने की योजना है। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1990-91 के दौरान सकल सिंचित क्षेत्र 61.78 मिलियन हैक्टेयर है;

(च) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, उत्पादन की जरूरतों और विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक भूमि को सिंचाई के तहत लाने के लिए योजना-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते है।